

12 नवंबर, 2022 को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप शिखर सम्मेलन - 2022 में गवर्नर के
साक्षात्कार के संपादित अंश

सुकुमार रंगनाथन

सभी को नमस्कार। मेरे साथ हैं श्री शक्तिकांत दास, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है; वे भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं। और मुझे लगता है कि हम सभी यह बेझिझक कह सकते हैं कि जब भी वे अपनी पॉलिसी पेश करने के लिए टेलीविज़न पर आते हैं, तो उनकी आवाज़ हमेशा भरोसा दिलाने वाली होती है - खास तौर पर पिछले दो सालों में, महामारी के दौरान।

बैंक ने हमें एक बहुत ही मुश्किल दौर से निकालने में मदद की है, और आगे भी कई चुनौतियाँ हैं; इसलिए वे और मैं इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यह एक ऐसा सत्र है जिसमें हम दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। इसलिए, आपको अपनी मेज़ पर कुछ कार्ड मिलेंगे। कृपया उन कार्डों पर अपने सवाल और अपना नाम लिख दें। कुछ लोग आकर वे कार्ड आपसे ले जाएँगे; मैं उन सवालों को छाँटूँगा और केवल वही सवाल पूछूँगा, जो मुझे लगता है कि इस सभा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी साबित होंगे।

श्री दास, मैं अपनी बात एक बड़े सवाल से शुरू करना चाहूँगा - और वह सवाल है हमारी अर्थव्यवस्था। इस बारे में आपका क्या आकलन है? आपको क्या लगता है कि अर्थव्यवस्था किस दिशा में आगे बढ़ रही है? आपको अर्थव्यवस्था की कौन-सी बातें अच्छी लग रही हैं? और आपको इसमें कमज़ोरियाँ कहाँ-कहाँ नज़र आ रही हैं?

शक्तिकांत दास

भारतीय अर्थव्यवस्था मज़बूत बनी हुई है। आप पूरी दुनिया को देखें कि दूसरी अर्थव्यवस्थाएँ कहाँ खड़ी हैं, और उन्हें किस तरह के तनाव से गुज़रना पड़ा है। पूरी दुनिया ने कई झटकों का सामना किया है, और मैं इन्हें तीन झटके कहता हूँ: कोविड-19 महामारी, फिर यूक्रेन में युद्ध, और अब वित्तीय बाज़ार में उथल-पुथल। वित्तीय बाज़ार में यह उथल-पुथल मुख्य रूप से दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा एक साथ अपनाई गई सख्त मौद्रिक नीति के कारण पैदा हुई है, खासकर अमेरिका के फेडरल रिज़र्व (यूएस फेड) के नेतृत्व वाले विकसित देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा। ज़ाहिर है, इसका असर भारत सहित उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ रहा है। दुनिया जिस तरह की लगातार उथल-पुथल से गुज़री है, उसमें आज यूरोपीय संघ मंदी जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। वे मंदी के कगार पर हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएँ भी

हैं कि वे इससे बच जाएँगे। संयुक्त राज्य अमेरिका स्थिर बना हुआ है, लेकिन कुछ अन्य देश भी हैं जहाँ विकास की गति धीमी हो गई है।

जहाँ तक भारत की बात है, इसकी अर्थव्यवस्था, समग्र व्यापक आर्थिक बुनियादी बातें, और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता - ये सभी पहलू मजबूत बने हुए हैं। बैंकिंग क्षेत्र - यानी वित्तीय क्षेत्र - स्थिर है, क्योंकि बैंकिंग, गैर-बैंकिंग ऋणदाताओं, या वित्तीय क्षेत्र के अन्य प्रमुख खिलाड़ियों से जुड़े सभी मापदंड स्थिर हैं। कुल मिलाकर, भारत का वित्तीय क्षेत्र स्थिर है। मौजूदा संदर्भ में, सकल आँकड़े अच्छे दिख रहे हैं। हमारा अनुमान है कि इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 7.0% की दर से बढ़ेगी। आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि चालू वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 6.8% की दर से बढ़ेगी। यह भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाता है।

महंगाई को लेकर हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। अगर आप हमारे लक्ष्य को देखें, तो इसकी ऊपरी सीमा लगभग 6.0% है। महंगाई के जो पिछले आंकड़े सितंबर महीने के लिए जारी किए गए थे, वे 7.4% थे। हमें उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के आंकड़े, जो सोमवार को जारी किए जाएंगे, 7% से कम होंगे।

महंगाई एक चिंता का विषय है, जिससे हम अब प्रभावी ढंग से निपट रहे हैं। पिछले छह या सात महीनों में, हमने कई कदम उठाए हैं। हमने ब्याज दरें बढ़ाई हैं, और सरकार ने भी आपूर्ति-पक्ष से जुड़े कई उपाय किए हैं।

कुल मिलाकर, संक्षेप में कहें तो, भारत के मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादी सिद्धांत मजबूत और लचीले बने हुए हैं। विकास की संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं। भारत ऐसे समय में जी-20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, जो शायद आधुनिक समय का सबसे चुनौतीपूर्ण वर्ष है; और हम कई अन्य देशों की तुलना में अधिक मजबूत मैक्रोइकोनॉमिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहे हैं।

सुकुमार रंगनाथन

आपने महंगाई के बारे में बात की, और अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार, केंद्रीय बैंक के तौर पर आपके अधिकार क्षेत्र का एक हिस्सा महंगाई का प्रबंधन करना है। आपने सरकार को एक पत्र भेजा है जिसमें महंगाई के प्रबंधन की पूरी प्रक्रिया और यह बताया गया है कि यह अभी भी तय सीमा से ऊपर क्यों है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपने उस पत्र में क्या कहा है? या क्या वह जानकारी गोपनीय है?

शक्तिकांत दास

हमने पत्र में क्या लिखा है, मुझे लगता है कि कोई भी इसका अंदाज़ा लगा सकता है। कानून के अनुसार, जब लगातार तीन तिमाहियों तक महंगाई 6% से ऊपर बनी रहती है, तो इसे मौद्रिक नीति की विफलता माना जाता है, और रिज़र्व बैंक को सरकार को एक पत्र लिखकर तीन मुख्य बातें बतानी होती हैं:

- i) ऐसा किन कारणों से हुआ है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या हैं?
- ii) इसे 6% से नीचे और 4% के लक्ष्य दर के करीब लाने के लिए रिज़र्व बैंक क्या कदम उठाने का प्रस्ताव करता है? और,
- iii) वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर हमें उम्मीद है कि महंगाई वापस लक्ष्य स्तर पर आ जाएगी?

तो, हमने मोटे तौर पर उन कारणों को समझाया है जिनके कारण ऐसा हुआ। मैंने कई मौकों पर इस बारे में बात की है। लगभग एक हफ़ता पहले, मैंने मुंबई में एक कॉन्फ्रेंस में भी बात की थी, जहाँ मैंने समझाया था कि भारत में महंगाई क्यों बढ़ी।

इस साल फरवरी में, जब हम मौद्रिक नीति समिति में मिले थे, तो हमारा इन्फ्लेशन का अनुमान -जो बाज़ार और पेशेवराना अनुमान लगाने वालों के अनुमान से अलग नहीं था - यह था कि 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा औसत इन्फ्लेशन लगभग 4.5% रहेगा। हमने कच्चे तेल की कीमत अमरीकी \$100 प्रति बैरल होने पर भी दबाव परीक्षण किए थे, और हमने पाया कि कच्चे तेल की कीमत अमरीकी \$100 प्रति बैरल होने पर भी, मुद्रास्फीति ज़्यादा से ज़्यादा 5% रहेगी। फरवरी में हमने यही अनुमान लगाया था। फिर 24 फरवरी को रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, और ज़ाहिर है, इससे पूरी तस्वीर ही बदल गई। उसके बाद, कच्चे तेल की कीमत अमरीकी \$130 प्रति बैरल तक पहुँच गई, और फिर घटकर अमरीकी \$120 प्रति बैरल पर आ गई। यह काफी समय तक अमरीकी \$120-110 प्रति बैरल के आस-पास बनी रही। अब, यह अमरीकी \$100 प्रति बैरल से नीचे आ गई है, लेकिन इसकी कीमत अमरीकी \$93-96 प्रति बैरल के बीच बनी हुई है। इसलिए, फरवरी में ऐसा लग रहा था कि मुद्रास्फीति पूरी तरह से नियंत्रण में है, और भारत 4% के लक्ष्य तक पहुँचने की सही राह पर है। लेकिन भू-राजनैतिक संकट, वस्तुओं की कीमतों में अचानक उछाल, खाने के तेल की कीमतों में अचानक उछाल, अनाज की कीमतों में अचानक उछाल - उदाहरण के लिए, गेहूँ। हमारे पास गेहूँ का बेशी स्टॉक है, लेकिन भारत में भी गेहूँ की कीमतें बढ़ गईं, क्योंकि हम एक पूरी दुनिया का हिस्सा हैं। गेहूँ की अंतरराष्ट्रीय कीमतें इसलिए बढ़ गईं, क्योंकि ब्लैक सी क्षेत्र से दुनिया के बाकी हिस्सों में गेहूँ का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। इसलिए, हम पर बड़े

बाहरी कारकों का असर पड़ा, और मुद्रास्फीति की पूरी तस्वीर में एक खास बदलाव आ गया। ये तीन बातें हैं; हमने बताया है कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी दो पहलुओं को मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूँ।

सुकुमार रंगनाथन

अगर तेल की कीमतें वहीं रहती हैं जहाँ वे अभी हैं, या वे उसी दायरे में घूमती रहती हैं जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि वे रहेंगी - जो कि एक रूढ़िवादी अनुमान लगता है, है ना? मेरा मतलब है, अमरीकी \$95 प्रति बैरल की कीमत ऊपर भी जा सकती है। समस्या यह है कि हमें नहीं पता कि युद्ध के साथ क्या होने वाला है। यह एक ऐसा युद्ध लगता है जिसका कोई अंत नहीं है और वैश्विक मुद्रास्फीति भी कम नहीं हो रही है। पहले से ही इस बात पर कुछ चर्चा हो रही है कि शायद हमें अपनी मुद्रास्फीति सीमा को संशोधित करने की ज़रूरत है - वह सीमा जो हमने तय कर रखी है। शायद भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्य को ऊपर की ओर संशोधित करने की ज़रूरत है। इस बारे में आपकी क्या राय है?

शक्तिकांत दास

इस लक्ष्य को 4% पर रखने का एक कारण है। रिज़र्व बैंक में एक आंतरिक समिति थी जिसने विस्तृत विश्लेषण किया और पाया कि 4% का मुद्रास्फीति लक्ष्य, जिसमें प्लस-माइनस 2% की कीमत सीमा हो - यानी हमारे पास 2% से 6% तक की एक सीमा हो - वह सही है। आरबीआई के शोध में उस समय यह पाया गया था - और आज भी यह बात सही साबित होती है - कि भारत के लिए 6% से ऊपर की मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए हानिकारक होगी। यह उल्टा असर करने वाली होगी क्योंकि यह एक नकारात्मक चक्र के माध्यम से काम करेगी। अगर मुद्रास्फीति 6% से ऊपर जाती है, तो वित्तीय बचत पर बुरा असर पड़ेगा। निवेश के माहौल को भी चोट पहुँचेगी। अगर मुद्रास्फीति लंबे समय तक 6% से ऊपर बनी रहती है, तो भारत अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा खो देगा।

इसलिए, 6% से ऊपर की कोई भी मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए हानिकारक है। इसीलिए, 6% को ऊपरी सहनशीलता सीमा के रूप में रखा गया है। यह तथ्य कि हमारे पास 4% और 6% के बीच एक सहनशीलता सीमा मौजूद है, आरबीआई को तनावपूर्ण समय के दौरान उपयोग करने के लिए पर्याप्त नीतिगत गुंजाइश देता है - जैसा कि हमने कोविड-19 महामारी के दौरान किया था। हालाँकि उस समय मुद्रास्फीति लगभग 5.0-5.5% थी, फिर भी मौद्रिक नीति समिति ने बहुत सोच-समझकर और बिल्कुल सही तरीके से उच्च मुद्रास्फीति को सहन करने का निर्णय लिया; क्योंकि कोविड के दौरान, प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को सहारा देना थी - जिसके लिए चलनिधि को आसान रखना और ब्याज दरों को कम रखना ज़रूरी था।

कोविद के दौरान, जब कोविद अभी खत्म नहीं हुआ था; जब अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत ज़्यादा दबाव झेल रही थी और भारत में लंबे समय बाद नकारात्मक वृद्धि हुई थी; वह समय मौद्रिक नीति को सख्त करने का नहीं था। इसलिए 4 से 6% के बीच की इस सीमा ने हमें मौद्रिक नीति को अर्थव्यवस्था के लिए सहायक बनाए रखने की छूट दी। हमने महंगाई से बाद में निपटने का फैसला किया, यानी जब हालात काबू में आ जाएं। जब हमने इस साल अप्रैल में अपने रुख में बदलाव करना शुरू किया, तो पिछले साल, यानी 2021-22 के लिए वृद्धि दर 7.7% थी। आपके मुख्य सवाल पर वापस आते हुए, क्या यह पूरी व्यवस्था को बदलने का समय है? मैं कहूंगा कि 6%, यानी 2 से 6% की सीमा, जिसमें 4% मुख्य लक्ष्य है, आर्थिक रूप से बहुत मायने रखती है। हमें लक्ष्य को बदलने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम उसे हासिल नहीं कर पाए हैं। हम समय के साथ महंगाई को 4% तक नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं; लेकिन मैं आपकी बात पर भी गौर करता हूँ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अब एक बहस शुरू हो रही है; मैं इतनी जल्दी उस बहस में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि हमें इसका और ज़्यादा विस्तार से अध्ययन करने की ज़रूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अब यह बहस शुरू हो रही है कि हमने लंबे समय तक कम ब्याज दरें रखीं और इसे 'लंबे समय तक कम' कहा गया। अब यह बहस शुरू हो रही है कि क्या हम 'लंबे समय तक ज़्यादा' के दौर में प्रवेश कर रहे हैं? क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरें बहुत लंबे समय तक ज़्यादा बनी रहेंगी? तब आपके सामने एक चुनौती होगी, और मुझे लगता है कि हर देश को अपने स्तर पर यह विश्लेषण करना होगा कि वे इस बारे में क्या करना चाहते हैं। यदि ज़्यादा महंगाई का लंबा दौर कुछ संरचनात्मक कारकों के कारण है, तो देशों को इस पर अपने स्तर पर विचार करने की ज़रूरत है। जहां तक भारत का सवाल है, मैं कहूंगा कि हम मौजूदा 4% के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं, जो बहुत मायने रखता है। यह हमें संकट की स्थितियों और कोविद जैसे झटकों से निपटने के लिए पर्याप्त छूट देता है, जिनका हमें सामना करना पड़ता है। सुकुमार रंगनाथन आपका यह पॉइंट कि क्या यह मुद्दा स्ट्रक्चरल है या नहीं, मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके बाद जो सवाल उठता है, वह बस यह है कि जिन झटकों की आपने बात की, यानी बाहरी कारक, क्या वे इतने अभूतपूर्व हैं कि हमें बदलाव करने के बारे में सोचना चाहिए? या आपको लगता है कि ये ऐसे झटके हैं जिनका सामना देश के तौर पर हमने पहले भी किया है और फिर से कर सकते हैं?

शक्तिकांत दास

नहीं, अभी बहुत जल्दी है। असल में, मैं नहीं चाहूंगा कि यह बहस समय से पहले शुरू हो जाए। मुझे लगता है कि इस बहस में पड़ना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। इसका मतलब सिर्फ यह होगा कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय बैंकों की प्रतिबद्धता कम हो जाएगी। इस बहस में पड़ने के लिए अभी बहुत जल्दी है। मेरा निजी तौर पर मानना है, और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का भी यही मानना है, कि हमें इतनी जल्दी इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस साल और अगले साल हालात कैसे रहते हैं। आगे चलकर, अगर हम देखते हैं कि दुनिया भर में महंगाई बनी रहती है—और महंगाई तब तक बनी रहेगी जब तक भू-राजनीतिक संकट जारी रहता है। बेशक, यह भू-राजनीतिक संकट की तीव्रता पर निर्भर करेगा। दूसरी ओर, अगर भू-राजनीतिक संकट कुछ ऐसा बन जाता है जिसमें युद्ध की आग तो सुलग रही हो, लेकिन कोई बड़ा भड़काव न हो, तो हालात शांत हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई चेन फिर से बहाल हो जाएंगी। 'फ्रेंड-शोरिंग' हो रही है। 'री-शोरिंग' हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सप्लाई चेन का पुनर्गठन हो रहा है। दुनिया इससे निपट लेगी। वैश्विक समुदाय इससे निपट लेगा। अगर भू-राजनीतिक संकट, भड़काव के चरम पर होने के बजाय, थोड़ा नरम पड़ जाता है और एक तरह के सुलगते हुए, दबे हुए युद्ध जैसा बना रहता है - जिसमें कहीं-कहीं छोटी-मोटी झड़पें होती रहें - और अगर सप्लाई चेन ठीक हो जाती है तो हम वैश्विक महंगाई का अंत उससे कहीं पहले देख पाएंगे, जितना मैंने पहले बताया था (जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि यह लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है)। इसलिए, इस बहस को शुरू करना अभी जल्दबाजी होगी, और यह अनावश्यक रूप से महंगाई के खिलाफ लड़ाई में केंद्रीय बैंकों की प्रतिबद्धता और विश्वसनीयता को कमजोर कर देगा।

सुकुमार रंगनाथन

यह बात आपने बिल्कुल सही कही है। मैं अब उस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़ूंगा। चलिए, अब हम रुपये की बात करते हैं। आपने बार-बार कहा है कि आरबीआई के पास रुपये-डॉलर विनिमय दर के लिए कोई पसंदीदा बैंड (दायरा) नहीं है, लेकिन आप समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाज़ार में दखल भी देते रहे हैं। क्या इस दखल के पीछे कोई मध्यावधि या दीर्घावधि की कोई खास रणनीति या तरीका है? आप कब दखल देने का फैसला करते हैं? और आप ऐसा क्यों करते हैं?

शक्तिकांत दास

हमारा दखल रोज़ाना के घटनाक्रमों पर निर्भर करता है। दो दिन पहले, अमरीकी सीपीआई महंगाई के आंकड़े आए थे, और रुपया एक रुपये मज़बूत होकर 81.80 रुपये से गिरकर 80.80 रुपये प्रति डॉलर पर आ गया था। रोज़ाना के आधार पर, कई तरह के घटनाक्रम होते रहते हैं। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बनती हैं जब कोई कहीं कोई बयान दे देता है, या किसी विकसित देश से कोई बयान आता है, और उसका असर बाज़ार पर पड़ता है। हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि रोज़ाना के आधार पर किस तरह का फ़लो - यानी इनफ़्लो और आउटफ़लो - हो रहा है। कई इनफ़्लो और आउटफ़लो का अंदाज़ा लगाना आसान होता है, और हम उनका पहले से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं; लेकिन कुछ ऐसे इनफ़्लो और आउटफ़लो भी होते हैं जिनका पहले से कोई अंदाज़ा नहीं होता - चाहे वे अंदर की ओर आ रहे हों या बाहर की ओर जा रहे हों। हमारी रणनीति रोज़ाना के आधार पर तय की जाती है, जो एक व्यापक मूल सिद्धांत के दायरे में आती है, और जिसके मुख्य रूप से तीन उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है - करेंसी की चाल में होने वाली अत्यधिक अस्थिरता को रोकना। हम ऐसी स्थिति नहीं आने दे सकते कि अचानक, महज़ 2-3 दिनों के भीतर ही, रुपये के विनिमय दर में भारी गिरावट आ जाए। इसलिए, हमारा पहला उद्देश्य है - अत्यधिक अस्थिरता को रोकना, और यह सुनिश्चित करना कि रुपये की विनिमय दर में दोनों ही स्थितियों में - चाहे रुपया मज़बूत हो रहा हो या कमज़ोर - एक व्यवस्थित और सुचारु बदलाव आए।

अगर आपको याद हो, जब महामारी वाले साल 2020-21 में भारी मात्रा में पैसा आया था, उसी समय हमने अपने रिज़र्व बढ़ाए थे। हम बाज़ार से डॉलर खरीद रहे थे और हमने अपने रिज़र्व बढ़ाए, क्योंकि हम जानते थे कि जो रिज़र्व इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, वे किसी न किसी मोड़ पर वापस भी चले जाएँगे और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। रिज़र्व लगभग अमरीकी \$400 बिलियन से बढ़कर अमरीकी \$642 बिलियन तक पहुँच गए थे, जो कि सबसे ऊँचा स्तर था। हमने ये अमरीकी \$240 बिलियन इसलिए जमा किए थे, क्योंकि हम जानते थे कि हालात कभी भी पलट सकते हैं और तब हमें बाज़ार को डॉलर देने पड़ सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया, जब बाज़ार में डॉलर की कोई सप्लाई नहीं थी; सिर्फ़ रिज़र्व बैंक ही डॉलर की सप्लाई कर रहा था। इसलिए, हमने बाज़ार में दखल देना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि हम डॉलर बेच रहे थे।

अब, कुछ लोगों ने यह टिप्पणी की कि आरबीआई इन रिज़र्व का इस्तेमाल बिना सोचे-समझे कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने ये रिज़र्व सिर्फ़ बुरे वक़्त के लिए जमा किए थे। जब बारिश होती है, तो आपको अपनी छतरी निकालनी पड़ती है और उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। हमने रिज़र्व सिर्फ़ इसलिए जमा नहीं किए थे कि उन्हें रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया

में एक शोपीस की तरह सजाकर रखा जाए। इस समय भी, हमारे रिज़र्व बहुत ही सुरक्षित और संतोषजनक स्थिति में हैं।

तो, विदेशी मुद्रा बाज़ार में दखल देने का पहला मकसद यह पक्का करना है कि विनिमय दर में बदलाव एक व्यवस्थित तरीके से हो। दूसरा मकसद है बाज़ार की उम्मीदों को स्थिर रखना। अगर रिज़र्व बैंक या केंद्रीय बैंक बाज़ार में दखल नहीं देता है, तो बाज़ार यह मान लेता है कि रुपया बस कमज़ोर होता जाएगा, और रिज़र्व बैंक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वह इस मामले में पूरी तरह से तटस्थ है। इससे रुपये की गिरावट और भी तेज़ हो जाएगी। इसलिए, हमें दोनों ही स्थितियों में बाज़ार की उम्मीदों को स्थिर रखना होगा - चाहे रुपया मज़बूत हो रहा हो या फिर कमज़ोर पड़ रहा हो। तीसरा, किसी भी सिस्टम की पूरी वित्तीय स्थिरता के मूल में एक स्थिर विनिमय दर व्यवस्था होती है। यही मुख्य कारक है, क्योंकि अगर आपकी करेंसी में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल होती है, तो इसका असर आयातकों पर पड़ेगा, निर्यातकों पर पड़ेगा, निवेशकों पर पड़ेगा और इससे कई तरह की रुकावटें पैदा होंगी, जिनका नतीजा आखिरकार वित्तीय क्षेत्र में अस्थिरता के रूप में सामने आएगा। इसलिए, तीसरा और मुख्य उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना है, जिसके लिए विनिमय दर प्रणाली में स्थिरता ज़रूरी है।

सुकुमार रंगनाथन

आपने रुकावटों की बात की, और टेक्नोलॉजी तथा नए बिज़नेस मॉडल वित्तीय प्रणाली में अपने आप में रुकावटें पैदा करने वाले तत्व हैं। नए ज़माने के वित्तीय उत्पादों और कंपनियों को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक का क्या नज़रिया है? इस नज़रिया को एक तरफ तो सावधानी, सुशासन और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन बनाना होता है, और दूसरी तरफ देश में फिनटेक के क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना होता है?

शक्तिकांत दास

रिज़र्व बैंक इनोवेशन (नवाचार) को बहुत बढ़ावा देता है। लेकिन हर इनोवेशन को, जब उसे कमर्शियल बनाया जाता है और एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी या फाइनेंशियल सिस्टम के हिस्से के तौर पर लागू किया जाता है, तो उसे ठीक से रेगुलेट किया जाना ज़रूरी है। यह एक समस्या वाला क्षेत्र रहा है। ग्राहकों को परेशान करने और बहुत ज़्यादा ब्याज़ दरें वसूलने की शिकायतें मिली थीं। कुछ मामलों में कर्ज़ लेने वालों को भी परेशान किया गया। यह समस्या खासकर कोविड के दौरान ज़्यादा महसूस हुई, जब शायद लॉकडाउन वगैरह की वजह से, बिना मंजूरी वाले कर्ज़ देने वालों ने पहले से मंज़ूर कर्ज़ देना शुरू कर दिया और लोगों ने कर्ज़ लेना शुरू कर दिया। उस समय, जून 2020 में ही, हमने सभी संस्थाओं के लिए एक 'फेयर प्रैक्टिसेस

कोड' (निष्पक्ष व्यवहार संहिता) जारी किया था, और उसके बाद हमने एक समिति बनाई। लगभग 6 महीने पहले, हमने डिजिटल लेंडिंग के लिए अपने दिशानिर्देश जारी किए थे। हमने डिजिटल लेंडिंग के लिए एक नियामकीय ढांचा जारी किया है, जिसका मुख्य मकसद ग्राहकों की सुरक्षा और कर्ज प्रोडक्ट में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। हमने कहा है कि हर डिजिटल लेंडर के पास एक प्रमुख तथ्य विवरण 'की फैक्ट स्टेटमेंट' होना चाहिए, जिसमें ब्याज दर के साथ-साथ अन्य सभी शुल्क (जिनमें कुल लागत भी शामिल हो) सालाना आधार पर साफ़-साफ़ बताए गए हों। होता यह है कि जब कोई आपको 100 रुपये देता है और ब्याज के तौर पर रोज़ाना 1 रुपया चुकाने को कहता है, तो यह बहुत आकर्षक लगता है; लेकिन 100 रुपये पर रोज़ाना 1 रुपया, इसका मतलब है रोज़ाना 1% ब्याज। अगर आप इसकी गणना सालाना आधार पर करें, तो यह बहुत ज़्यादा (असहनीय) हो जाता है। हमने कहा है कि ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए, ये दिशानिर्देश बहुत मज़बूत हैं, और बाज़ार में इनका अच्छा स्वागत हुआ है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई शिकायत आती है, तो उसके समाधान के लिए एक 'शिकायत अधिकारी' होना चाहिए। डिजिटल लेंडर को ही ये शिकायतें स्वीकार करनी होंगी।

लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इसके बावजूद, अभी भी कुछ गैर-कानूनी डिजिटल ऐप्स मौजूद हैं। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो अभी भी ऋण देने का काम जारी रखे हुए हैं। हमने कानून लागू करने वाली एजेंसियों के साथ विस्तार से बातचीत की है। इस तरह की संस्थाओं से निपटने का काम कानून लागू करने वाली एजेंसियों का ही है। जब भी ऐसी कोई बात हमारे संज्ञान में आती है, तो हम तुरंत उसे संबंधित कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सौंप देते हैं, ताकि वे ऐसी संस्थाओं के खिलाफ कानूनी और अन्य ज़रूरी कार्रवाई कर सकें।

सुकुमार रंगनाथन

आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 'प्रीडेटरी लेंडिंग' (शोषणकारी तरीके से लोन देना) - खासकर छोटे शहरों में - एक बहुत बड़ी समस्या है। यह उन ग्राहकों के बीच भी फैली हुई है जिन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती; ठीक वैसे ही, जैसे पहले कई क्रिप्टो एक्सचेंज काम किया करते थे, है ना? मुझे याद है, उनमें से किसी एक एक्सचेंज के सीईओ मुझसे मिलने आए थे। वे बड़े गर्व से उन लोगों के बारे में बता रहे थे जो छोटे शहरों में क्रिप्टोकॉरेंसी में निवेश कर रहे हैं। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि ये वे लोग हैं जिन्हें इससे जुड़े जोखिमों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब सीबीडीसी (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) के बारे में क्या कहेंगे? इसकी एक प्रायोगिक परियोजना अभी चल रही है। हमें इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताइए। मूल रूप से, क्या डिजिटल करेंसी का कोई वास्तविक व्यावहारिक लाभ है? या फिर यह सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसे 'होना अच्छा है' की श्रेणी में रखा जा सकता है?

शक्तिकांत दास

नहीं, इसका एक बुनियादी फ़ायदा है। दुनिया बदल रही है। जिस तरह से कारोबार किया जाता है, वह बदल रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। आपको समय के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। यह पूरे मामले को देखने का एक आम नज़रिया है। ज़्यादा खास तौर पर कहें तो, नोटों, करेंसी नोटों, और कागज़ी नोटों की छपाई में लागत आती है। इसमें छपाई की लागत, कागज़ की लागत, लॉजिस्टिक्स की लागत, स्टोरेज की लागत, और पूरा लॉजिस्टिक्स वगैरह शामिल है; इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा लागत लगती है। आगे चलकर, यह कागज़ी करेंसी के मुकाबले बहुत कम खर्चीला होगा। यह पहली बात है। दूसरी बात, यह कुछ ऐसा है जो सीमा-पार लेन-देन और सीमा-पार भुगतानों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। आज, जब पैसा एक देश से दूसरे देश में भेजा या ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, औसत शुल्क लगभग 6% होता है। जब सीबीडीसी आएगा, मान लीजिए देशों के किसी समूह में, तो लागत असल में बहुत ही मामूली होगी। यह हमारे सिस्टम और उनके सिस्टम के ओवरहेड्स की लागत होगी। यह काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और यह तुरंत होगी। बेशक, आप यह सवाल पूछ सकते हैं कि अभी भी यूपीआई के तहत, हम पैसे के रियल-टाइम ट्रांसफ़र के लिए काम कर रहे हैं। असल में, भारत और सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, और अन्य खाड़ी देशों जैसे कई दूसरे देशों के बीच, यूपीआई को पहले से ही जोड़ा जा रहा है ताकि भारत और उन देशों के बीच पैसे का रियल-टाइम ट्रांसफ़र हो सके। आप कह सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन यूपीआई एक भुगतान प्रणाली है, जबकि यह एक करेंसी सिस्टम है। यूपीआई भुगतानों को होने में मदद करता है। यहाँ खुद करेंसी - केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी - अंतरित होगी। यह कम खर्चीला है, यह अंतरराष्ट्रीय भुगतानों, सीमा-पार भुगतानों में मदद करेगा, और यह निर्यात करने वालों और आयात करने वालों के लिए अच्छा होगा। मुझे लगता है कि भविष्य टेक्नोलॉजी का है। ऐसा भी समय आ सकता है जब आधी दुनिया या आधी से ज़्यादा दुनिया डिजिटल करेंसी पर होगी और आप कागज़ी करेंसी पर नहीं रह सकते। आपको बदलते हुए तकनीकी विकास के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा।

सुकुमार रंगनाथन

अब एक थोड़े बड़े सवाल की ओर बढ़ते हैं। महामारी से पहले, न सिर्फ़ भारत में, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में केंद्रीय बैंकों की स्वायत्तता और आज़ादी, और सरकार की भूमिका को लेकर लगातार बहस चलती रहती थी। हमने तब से जो देखा है, वह यह है कि केंद्रीय बैंकों और सरकारों को अब ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर काम करना पड़ रहा है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं?

शक्तिकांत दास

जब मैंने 12 दिसंबर 2018 को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया जॉइन किया था; तो पहले ही दिन मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी रिज़र्व बैंक, और सरकार, जो कि फिस्कल अथॉरिटी है, उनके बीच तालमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही अर्थव्यवस्था के हित में काम कर रहे हैं। दोनों ही जनता की भलाई सुनिश्चित करने के काम में लगे हैं। इन दोनों संस्थाओं को आपस में बातचीत करनी चाहिए और एक-दूसरे से जुड़ना चाहिए। सलाह-मशविरे की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही अर्थव्यवस्था से जुड़े मामलों को देख रहे हैं। केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के बारे में, मैं आपको बहुत साफ़-साफ़ बता दूँ कि जहाँ तक भारत का सवाल है, स्वायत्तता का क्या मतलब है? स्वायत्तता का मतलब है फ़ैसले लेने में स्वायत्तता। सरकार और आरबीआई के बीच, और आरबीआई और सरकार के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता है; सरकार को वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और ऐसी ही कई दूसरी चीज़ों के लिए आरबीआई की ज़रूरत पड़ती है। रिज़र्व बैंक को भी सरकार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें कानूनी बदलावों की ज़रूरत होती है।

मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पिछले 3-4 सालों में कई कानूनी बदलाव किए गए हैं। हमें एनबीएफसी को रेगुलेट करने, शहरी सहकारी बैंकों की समस्याओं से निपटने और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को रेगुलेट करने के लिए अतिरिक्त अधिकार मिले हैं; जिन्हें पहले राष्ट्रीय आवास बैंक विनियमित करता था। उन्हें आरबीआई को सौंप दिया गया, क्योंकि एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एक एनबीएफसी के बीच कोई अंतर नहीं होता। इसलिए, हमें सरकार के सहयोग की भी ज़रूरत है। आखिरकार, अगर अर्थव्यवस्था को अच्छा प्रदर्शन करना है, तो राजकोषीय और मौद्रिक, दोनों ही अधिकारियों को आपस में घनिष्ठ तालमेल बिठाकर काम करना होगा। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह तालमेल और बातचीत पूरी दुनिया में होती है। यह सिर्फ़ भारत की ही कोई अनोखी बात नहीं है। यह पूरी दुनिया में होता है, लेकिन समय-समय पर बाहर से कई तरह की बेमतलब की आवाज़ें आती रहती हैं। ट्रेजरी और मौद्रिक प्राधिकरण के बीच; और दुनिया भर में वित्त मंत्रालयों तथा मौद्रिक प्राधिकरणों के बीच घनिष्ठ तालमेल और लगातार बातचीत होती रहती है। इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। खासकर कोविड के समय में, यहाँ तक कि पारंपरिक रूप से नियमों के पक्के लोग भी अब यह मानने लगे हैं कि कोविड जैसी तनावपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए, मौद्रिक और राजकोषीय अधिकारियों के बीच उचित तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। तालमेल और बातचीत का मतलब यह नहीं है कि स्वायत्तता से कोई समझौता किया जाए। कोई भी एक-दूसरे के काम में दखल नहीं देता, बल्कि हम अपने विचार आपस में साझा करते हैं। महँगाई के मुद्दे को ही देख लीजिए। जहाँ एक तरफ़ हमने चलनिधि को नियंत्रित करके, ब्याज दरें बढ़ाकर और कई अन्य

उपायों के ज़रिए कई मौद्रिक कदम उठाए हैं; वहीं दूसरी तरफ़ सरकार ने आपूर्ति-पक्ष से जुड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि पेट्रोल और डीज़ल पर कर कम करना, खाने के तेल और दालों पर आयात शुल्क घटाना; जिनका महँगाई पर सकारात्मक असर पड़ा है। इसलिए, इन दोनों के बीच एक-दूसरे पर निर्भरता मौजूद है।

सुकुमार रंगनाथन

आप सबको मिलकर काम करना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, गवर्नर साहब। आपको यहाँ पाकर बहुत खुशी हुई। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक यह महसूस करते हुए वापस जाएँगे कि हमारे देश की बागडोर एक स्थिर और भरोसेमंद हाथों में है। धन्यवाद।

शक्तिकांत दास

बहुत-बहुत धन्यवाद।